

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 029/2017 (GCMS 2017/00117)	दायर दिनांक 15.12.2017	निर्णय दिनांक 05.04.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

जितेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्ट**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट

-:: प्रथम अपील कार्यवाही 91 एल आर एक्ट निर्णय श्री न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय रावतभाटा प्रकरण संख्या 365/2017 निर्णय दिनांक 08.11.2017 बअनवान प्रकरण राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का भैंसरोडगढ़ बनाम जितेन्द्र सिंह :-

उपस्थिति :- श्री जितेन्द्र औझा
श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)

अधिवक्ता अपीलांट
अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

-:: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अप्रार्थी को आराजी संख्या 700 रकबा 0.08 का लगान 1 का 50 गुना 50.00 अक्षरें पचास रुपयें शास्ति आरोपित व भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश एवं 1 माह का सिविल कारावास का दण्ड का निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 का नोटिस जारी किया था परन्तु बिना सुनवाई के जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही सजा देने का व शास्ति देने का



निर्णय प्रदान कर दिया जो नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 700 के रकबा 0.08 किस्म बीड पर अपीलाण्ट द्वारा पत्थर की कोट बनाकर अतिक्रमण करना बताया है, परन्तु बिना सुनवाई के व साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिये बिना ही पटवारी गलत रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा गलत निर्णय पारित कर दिया। जब कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य सबुत के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए जो नहीं कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पत्रावली निपटाने का कार्य किया है जो उक्त निर्णय से स्पष्ट है। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सका। पटवारी हल्का की एक मात्र रिपोर्ट पर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जब कि अपीलांट ने कोई फसल नहीं हाकी है। पत्थर की कोट से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है, नहीं अपीलाण्ट ने कोई पत्थर की कोट कराई है। नहीं पुर्व में प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण किया है। जब कि अपीलांट जवाब पेश करने का अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवसर दिये बिना ही 1 माह का कारावास व शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट कोई पूर्व अतिकमी नहीं है, नहीं अपीलांट ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। अन्य तथ्य वक्त बहस अर्ज किये जाएंगे। आराजी वाके ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होने से अपील को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आप होने से न्यायालय आप में सादर प्रस्तुत है। अपील निश्चित न्यायशुल्क पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाया जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 1 माह का कारावास व शास्ति निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रावतभाटा का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार रावतभाटा के पत्रांक/राजस्व/2018/44 दिनांक 21.02.2018 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 365/2017 अनवानी सरकार बनाम जितेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह राठौड निवासी भैंसरोडगढ़, अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 30.03.2021 को प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया इस पर उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली की गई। प्रकरण में अपीलांट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956



पर उभयपक्षकारान की सहमति से कार्यवाही ड्रॉप की जाकर मूल अपील पर बहस पत्रावली की गई। अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अप्रार्थी को आराजी संख्या 700 रकबा 0.08 का लगान 1 का 50 गुना 50.00 अक्षरें पचास रुपयें शास्ति आरोपित व भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश एवं 1 माह का सिविल कारावास का दण्ड का निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 का नोटिस जारी किया था परन्तु बिना सुनवाई के जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही सजा देने का व शास्ति देने का निर्णय प्रदान कर दिया जो नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके ग्राम भैंसरोडगढ़ तहसील रावतभाटा की आराजी संख्या 700 के रकबा 0.08 किस्म बीड पर अपीलाण्ट द्वारा पत्थर की कोट बनाकर अतिक्रमण करना बताया है, परन्तु बिना सुनवाई के व साक्ष्य सबुत पेश करने का अवसर दिये बिना ही पटवारी गलत रिपोर्ट के आधार पर एक तरफा गलत निर्णय पारित कर दिया। जब कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य सबुत के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए जो नहीं कर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पत्रावली निपटाने का कार्य किया है जो उक्त निर्णय से स्पष्ट है। अपीलांट को सिविल कारावास की सजा एवं 50/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया गया जो तार्किक एवं विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक अपास्त फरमाये जावें। इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2017 प्रश्नगत आराजी पर लगातार अपीलांट द्वारा कब्जा कर अतिक्रमण के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, चूंकि विवादित आराजीयात किस्म बीड होकर राजकीय भूमि है जिस पर अतिक्रमण किये जाने पर अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के विधिक प्रावधानों के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है, इसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में किसी भी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारीज फरमाई जावें। इस पर बहस अपील के रिटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सका। पटवारी हल्का की एक मात्र रिपोर्ट पर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जब कि अपीलांट ने कोई फसल नहीं हाकी है। पत्थर की कोट से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है, नहीं



अपीलाण्ट ने कोई पत्थर की कोट कराई है। नहीं पुर्व में प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण किया है। जब कि अपीलांट जवाब पेश करने का अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवसर दिये बिना ही 1 माह का कारावास व शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट कोई पूर्व अतिकमी नहीं है, नहीं अपीलांट ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]



(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issued under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time- and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

विवादित भूमि किस्म बीड राजकीय भूमि दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार रावतभाटा ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के



अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) में अतिक्रमी को परिभाषित किया गया है। उक्त प्रावधान अधिनियम में निम्नानुसार प्रावधित किये गये हैं।

5(44) "Trespasser"

shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

विवादित आराजीयात आराजी संख्या 700 किस्म बीड के संबंध में अपीलांत यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट करने में असफल रहा है कि उक्त विवादित आराजीयात में अपीलांत का किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार निहित है, ऐसी स्थिति में अपीलांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) के तहत उक्त विवादित आराजीयात का अतिक्रमी है, किन्तु अपीलांत द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांत द्वारा उक्त विवादित आराजीयात पर अतिक्रमण नहीं किया गया है एवं ना ही कोई पत्थर की कोट बनाई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हत्का पटवारी भैंसरोडगढ द्वारा तहसीलदार रावतभाटा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अपीलांत द्वारा विवादित आराजीयात पर पत्थर की कोट व कंटीली झाडियां लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रमाणित है एवं पर्चा मौका भी बनाया गया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रावतभाटा के पास कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार रहे हैं। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.10.2017 को अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। इस पर दिनांक 08.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी करार दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2017 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांत को प्रश्नगत आराजीयात का अतिक्रमी करार दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अपीलांत द्वारा उक्त अतिक्रमण पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को 1 माह सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2017 में आंशिक हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2017 को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।



उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण संख्या 365/2017 अनवानी सरकार बनाम जितेन्द्रसिंह पिता महेन्द्रसिंह राठौड निवासी भैंसरोडगढ़, अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2017 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट जितेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी भैंसरोडगढ़ को दी गई 1 माह सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) किया जाता है एवं शेष निर्णय को यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हाजरी बाबत जमानत/मुचलके निरस्त किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 05.04.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़